रेखा से नीचे हैं और हर विकास खंड में लगभग 600 (छः सौ) परिवारों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मैं भारत सरकार का ध्यान उन लोगों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि अधिक निर्धन हैं और हिमाचल के छोटे-छोटे नगरों में जहां कारपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी और स्माल टाउन कमेटी के क्षेत्र में आते हैं, इन्हें किसी प्रकार की आई.आर.डी. द्वारा सुविधा प्रदान नहीं है और ये लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं इस प्रभावशाली योजना से कोई भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग उक्त कमेटी क्षेत्रों की सीमा में आते हैं का सर्वेक्षण किया आए और जो सुविधा ग्रामीण निर्धन लोगों को प्राप्त है, उन्हें भी प्राप्त कराई जाए।

(v) Central direction sought to remove illegal shops and Kiosks from the Vicinity of Sarnath temple.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के बौद्ध तीर्थस्थल सारनाथ (वाराणसी) उत्तर प्रदेश का सौन्दर्य एवं रमणीकता स्थानीय गुमटियों एवं खोखों के कारण नष्ट एवं घूमिल हो रही है। विदेशी यात्रियों एवं पर्यटकों से ये दूकानदार मनमाने ढंग से पैसा वसूल करके तथा अभद्र व्यवहार करके राष्ट्र की छवि को विदेशियों की दृष्टि में गिरा रहे हैं। सारनाथ के इस विश्व-विख्यात स्थल का हमारे राष्ट्र नायक स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाखों रुपया व्यय करके दो हजार पांच सौवीं बुद्ध जयंती पर, उद्धार एवं सुन्दर कायाकल्प कराया गया है। आज भारत-भ्रमण पर आने वाले विदेशी पर्यटक राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकारी शिष्ट मण्डल 95 प्रतिशत सारनाथ में आते हैं जिससे हमारे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और ये विदेशी पर्यटक भारत की प्राचीन संस्कृति एवं बौद्ध तीर्थ स्थल को देखकर परम संतुष्ट होते हैं। इस स्थल पर राजकीय पथों एवं तीर्थ स्थलों की सड़क के दोनों किनारे अवैध रूप से सैकड़ों गुमटियां और खोखों का निर्माण करके वहां की सुन्दरता को नष्ट किया जा रहा है और दूकानदार विदेशी पर्यटकों को बसों और कारों से उतरते ही बुरी तरह घेर कर नकली मूर्तियां और अन्य माल खरीदने को बाध्य करते हैं। नगर महापालिका और वाराणसी विकास प्राधिकरण का ध्यान इन अवैध गुमटियों को हटाने हेतु दिलाने पर वे मौन हैं और कोई प्रभावी कार्यवाही अमल में नहीं लाते।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की गम्भीरता को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को तुरन्त निर्देश देकर सारनाथ से अवैध गुमटियों को हटवाए जिससे वहां की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा हो सके।

(vi) Acute Scarcity of kerosene in Midnapur district, West Bengal.

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore) : Sir, a large part of Midnapur district in West Bengal such as Itargram sub division, Midnapur sub division, Sadar, Kharagpur sub division are suffering from acute shortage of Kerosene. The IOC has unilaterally reduced the quota without consulting with anybody. This has caused sudden hardship for the people of the area which is a traditionally backward area inhabited by people belonging to SC/ST communities.

The Government immediately intervene and restore the old quota to end the avoidable hardship of the people of the area.

(vii) Demand for a 100 line Telephone Board for Hanumangarh (Rajasthan).

श्री बीरबल (गंगानगर) : हनुमानगढ़ टाउन में पिछले दो वर्षों से सौ टेलीफोन लगाने

का बोर्ड मंजूर हुआ पड़ा है । हर पल अधिकारीगण कोई-न-कोई बहानाकर बोर्ड नहीं आने की वजह से नए फोन नहीं दे रहे हैं । हनुमानगढ़ टाउन एक विकासशील कस्बा है जिसमें हर प्रकार के व्यवसाय, कारखाने और काश्तकार हैं तथा और भी जनता के द्वारा टेलीफोन की मांग चलती ही रहती है । करीब 80 लोग तो पिछले दो वर्षों से प्रतीक्षा सूची में रुपये जमा कर बोर्ड लगने की इंतजार में हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जनरल मैनेजर टेलीफोंस राजस्थान, जयपुर को आदेश देकर जल्द-से-जल्द सौ लाईन का एक बोर्ड हनुमानगढ़ में भिजवाने की व्यवस्था करें । इसके साथ-साथ मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप राजस्थान के जनरल मैनेजर टेलीफोन्स महोदय से पिछले दो वर्षों से मन्जूर शुदा बोर्ड के न लगने की जांच करवाने की कृपा करें ।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संचार मन्त्री की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने की कृपा करेंगे ।

(viii) Need for immediate negotiations with Kendriya Vidyalaya teachers to avoid proposed agitation.

SHRI AJIT BAG (Serampore) : Legitimate grievances of more than 25,000 teachers of about 500 Kendriya Vidyalayas spread all over the country are pending for a long time. Now, from 9th August, 1984 these teachers under the banner of All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association have decided to start an agitation which they had earlier postponed anticipating negotiated settlement of the issues involved.

These Kendriya Vidyalayas cater to the educational needs of the wards of Central Govenment employees with All India Transfer liability, both civilians and Defence personnel besides different categories of floating population and bulk of the credit for the rapid qualitative and quantitative growth of these schools goes to the teachers in the main. However, it is an irony that their genuine problems have remained unattended to. They have been expressing their difficulties and problems through various forms of peaceful agitations viz. Relay fast, Mass Casual Leave, Rallies, Submission of Memoranda etc. for the last three years but in vain. One of their main demands is for introduction of Joint Consultative system for collective bargaining as is in existence in Central Services. The other legitimate demand is for parity of wages with their counterparts in Union Territory of Delhi etc.

The Hon. Minister of Education and Social Welfare should immediately intervene and avoid the proposed agitation by the teachers of Kendriya Vidyalayas by arranging for negotiated settlement of the demands.

(ix) Establishing the proposed Railway Wagon and Coach Factory in Vidarbha (Maharashtra).

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : महाराष्ट्र सरकार ने एकमत होकर रेलवे मन्त्रालय से यह अनुरोध किया है कि प्रस्तावित रेलवे वैगन एवं कोच फैक्ट्री का निर्माण विदर्भ क्षेत्र में किया जाए । योजना आयोग ने बहुत पहले इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है । साथ ही नागपुर के बुटीबोरी एवं वर्धा के पुलगांव क्षेत्रों का रेल अधिकारियों और "राईट्स संस्था" द्वारा सर्वे किया जा चुका है । यह दोनों ही स्थान इसके लिए सर्वथा उपयुक्त हैं । यदि केन्द्र सरकार चाहती हो कि वह नो-इण्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण करेगी तो विदर्भ में ही गड़-चिरोली महाराष्ट्र का एकमेव नो-इंडस्ट्री जिला है तथा आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर इसका निर्माण करें । दांडेकर समिति, जो बैकलाग का मूल्यमापन करने के लिए आई थी, उसने भी विदर्भ में औद्योगिक बैकलाग होने की बात को स्वीकारा है ।